# ग्रेटर नोएडा का PRAGATI पार्क: रोबोटिक्स और AI के लिए प्रस्तावित ढाँचा

समाचार-संदर्भ: 27 अक्टूबर 2026 | प्रकाशन: 28 अक्टूबर 2026
प्रिलिम्स: PRAGATI, PPP, SPV | मुख्य परीक्षा: GS-3 विज्ञान-प्रौद्योगिकी, निवेश और रोजगार




मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

यह प्रस्तावित तकनीकी सुविधाओं का प्रतीकात्मक चित्र है, PRAGATI पार्क या उसकी किसी वास्तविक प्रयोगशाला की तस्वीर नहीं।

## खबरों में क्यों

DD News पर प्रकाशित PTI की रिपोर्ट और The Hindu की 27 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में लगभग 69.52 एकड़ में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका नाम **PRAGATI: Platform for Robotics and AI Growth Through Technology and Innovation** है।

रिपोर्टों में राज्य सरकार के वक्तव्य और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की जानकारी के आधार पर स्वदेशी रोबोटिक्स निर्माण, AI तकनीक, स्टार्टअप, निवेश और अनुसंधान को जोड़ने का उद्देश्य बताया गया है। यह **मंजूर परियोजना का प्रस्तावित ढाँचा** है, पूरी तरह तैयार या चालू पार्क की खबर नहीं।

## दो ज़ोन, अलग विकास-व्यवस्था

- **ज़ोन 1: आठ एकड़।** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) के माध्यम से विकास और संचालन प्रस्तावित है। SPV में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी 26% और चुने जाने वाले

औद्योगिक साझेदार की 74% होगी।

- **ज़ोन 2: 61.52 एकड़।** निजी उद्यम औद्योगिक इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में निवेश करेंगे। उद्धृत सरकारी वक्तव्य के अनुसार इस ज़ोन के विकास की पूँजीगत देनदारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।

इस परियोजना में PPP सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी साझेदार की संयुक्त व्यवस्था है। SPV उस व्यवस्था के अंतर्गत बनने वाली विशेष उद्देश्य की कंपनी है। दोनों शब्द पर्याय नहीं हैं। 26:74 अनुपात **इक्विटी हिस्सेदारी** का है, भूमि के क्षेत्रफल या पूरे पार्क में रोजगार के बँटवारे का नहीं।

## वित्तीय सहायता की अलग-अलग मदें

रिपोर्टों के अनुसार, ज़ोन 1 के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ₹21.1 करोड़ की इक्विटी देगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 30 वर्ष के लिए ₹126.2 करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण देगी। आठ एकड़ भूमि के लीज प्रीमियम की प्रतिपूर्ति निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राज्य के IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के माध्यम से प्राधिकरण को की जानी है।

ज़ोन 2 में भूमि-आवंटन के विकास शुल्क से मिलने वाले राजस्व के 5% के बराबर सेवा शुल्क और लागू GST की व्यवस्था SPV के लिए बताई गई है। **इक्विटी, ऋण और सेवा शुल्क अलग मदें हैं।** इन्हें जोड़कर बिना पूरे परियोजना दस्तावेज के "कुल परियोजना लागत" घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

## स्टार्टअप को किस तरह की सुविधाएँ मिल सकती हैं?

DD News/PTI की रिपोर्ट में रोबोटिक्स परीक्षण और प्रमाणन केंद्र, त्वरित प्रोटोटाइप निर्माण, AI कंप्यूटिंग अवसंरचना, मोशन-कैप्चर प्रणालियाँ और डेटा प्रयोगशालाएँ प्रस्तावित बताई गई हैं। स्टार्टअप और उद्यमियों को परीक्षण, प्रोटोटाइप और GPU-आधारित कंप्यूटिंग सुविधाएँ सुलभ दरों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

परीक्षण और डिजाइन को एक जगह जोड़ने से छोटे उद्यमों के लिए शुरुआती तकनीकी बाधाएँ घट सकती हैं। लेकिन वास्तविक लाभ उपयोग-शुल्क, उपकरणों की उपलब्धता, तकनीकी सहायता और उद्योग की माँग पर निर्भर करेगा। यह संभावित प्रभाव का विश्लेषण है, अभी हासिल परिणाम नहीं।

तकनीकी पृष्ठभूमि: न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और मस्तिष्क से प्रेरित चिप। यह संबंधित अध्ययन-विषय है; PRAGATI में किसी खास चिप या तकनीक के चयन का प्रमाण नहीं।

## रोजगार और समयसीमा को कैसे पढ़ें?

### अनुमान उपलब्धि नहीं है

पूरी क्षमता विकसित होने पर एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग ₹2,000 करोड़ के वार्षिक सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अनुमान बताया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इतने रोजगार बन चुके हैं। GVA का अनुमान परियोजना की आय, सरकारी राजस्व या स्वीकृत निर्माण-लागत का आँकड़ा भी नहीं है।

DD News/PTI के अनुसार, ज़ोन 1 में व्यावसायिक संचालन SPV के पंजीकरण से 36 महीने में शुरू करने का लक्ष्य है; जरूरत पड़ने पर अवधि अधिकतम 48 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। इसलिए "मंजूरी की तारीख से 36 महीने" लिखना सही नहीं होगा। औद्योगिक साझेदार का चयन, SPV पंजीकरण, भूमि-आवंटन, लीज दस्तावेज और निर्माण आगे की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

## परीक्षा के लिए विश्लेषण

यह परियोजना औद्योगिक नीति में साझा तकनीकी सुविधाओं और निजी निवेश के संबंध को समझाती है। उत्तर में चार प्रश्न उपयोगी होंगे: क्या सुविधाएँ छोटे स्टार्टअप तक पहुँचेंगी; क्या कौशल-प्रशिक्षण उद्योग की जरूरत से जुड़ेगा; क्या सार्वजनिक सहायता और निजी दायित्व स्पष्ट होंगे; और क्या प्रगति को निर्माण के साथ वास्तविक उपयोग, उत्पाद और रोजगार से भी मापा जाएगा?

किसी तकनीकी पार्क की सफलता केवल भूमि या घोषणा की संख्या से तय नहीं होती। समय पर संचालन, पारदर्शी साझेदार-चयन, परीक्षण-सुविधाओं का उपयोग और टिकाऊ व्यावसायिक माँग भी महत्त्वपूर्ण हैं।

## प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

### 1. प्रस्तावित PRAGATI पार्क के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(a) इसका पूरा 69.52 एकड़ क्षेत्र एक ही PPP ज़ोन में है
(b) ज़ोन 1 की SPV में प्राधिकरण और औद्योगिक साझेदार की इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 74% होगी
(c) ₹126.2 करोड़ को सरकारी अनुदान बताया गया है
(d) एक लाख से अधिक रोजगार पहले ही बन चुके हैं

▼ उत्तर और व्याख्या
**उत्तर: (b)।** आठ एकड़ का ज़ोन 1 PPP-SPV व्यवस्था में है; 61.52 एकड़ का ज़ोन 2 निजी निवेश के लिए है। ₹126.2 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण है। रोजगार संख्या पूरी क्षमता पर अनुमान है।

### 2. ज़ोन 1 में व्यावसायिक संचालन के 36 महीने के लक्ष्य का आरंभ-बिंदु क्या बताया गया है?

(a) मंत्रिमंडल की मंजूरी का दिन
(b) पहला रोजगार सृजित होने का दिन
(c) SPV का पंजीकरण
(d) ज़ोन 2 में अंतिम औद्योगिक इकाई खुलने का दिन

▼ उत्तर और व्याख्या
**उत्तर: (c)।** DD News/PTI की रिपोर्ट में समयसीमा SPV के पंजीकरण से जुड़ी है। जरूरत पड़ने पर अवधि अधिकतम 48 महीने तक बढ़ाने की बात है।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**तकनीकी पार्कों में साझा परीक्षण और कंप्यूटिंग सुविधाएँ नवाचार को कैसे सहारा दे सकती हैं? PRAGATI पार्क के प्रस्ताव के संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाओं और जवाबदेही की जरूरत पर चर्चा कीजिए।** (150 शब्द, 10 अंक)

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** मंजूर परियोजना और तैयार अवसंरचना का अंतर रखें।

**मुख्य भाग में:** साझा सुविधाएँ, स्टार्टअप की लागत, कौशल, निजी निवेश, स्पष्ट दायित्व और प्रगति-मूल्यांकन जोड़ें।

**निष्कर्ष में:** रोजगार और GVA को अनुमान मानते हुए परिणाम-आधारित समीक्षा सुझाएँ।

## स्रोत और सीमाएँ

- DD News/PTI, 27 अक्टूबर 2026: परियोजना, वित्त और समयसीमा का विवरण
- The Hindu, 27 अक्टूबर 2026: सरकारी वक्तव्य और वित्त मंत्री की जानकारी

यह लेख खुले समाचार-विवरणों में उद्धृत सरकारी जानकारी पर आधारित है। मूल मंत्रिमंडलीय आदेश, अनुबंध या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वित्तीय मदों को अंतिम कुल लागत, अनुमान को उपलब्धि या प्रस्तावित सुविधा को चालू सुविधा नहीं बताया गया है।